

बजटेंतर संसाधनों का विवरण (ईबीआर) (सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड्स और अन्य संसाधन)

मांग संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	2016-17 से 2021-22 वास्तविक	2022-23 ब.अ	2022-23 सं.अ.	2023-24 ब.अ
26	उच्चतर शिक्षा विभाग				
	उच्चतर शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुनरुद्धार (आरआईएसई)				
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना				
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय				
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी	20000.00			
62	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
	(i)पोलावरम सिंचाई परियोजना	6245.00			
	(ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनफिट्स प्रोग्राम एवं अन्य परियोजनाएं)	14670.80			
63	पेयजल और स्वच्छता विभाग				
	(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (ii)जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	12298.20			
71	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		शून्य	शून्य	शून्य
	(i) ग्रिड इन्टरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत ऑफ ग्रिड/संवितरित एवं विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा	1640.00			
	(ii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)				
78	पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय				
	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) परियोजनाएं	1000.00			
79	विद्युत मंत्रालय				
	(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य	29109.00			
	(ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि परियोजनाएं	5504.70			
87	ग्रामीण विकास विभाग				
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण	48819.60			
	<b>सकल जोड़</b>	<b>139287.30</b>			

**टिप्पणी:**

- (i) रेल मंत्रालय को अपने राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण के माध्यम से लगभग ₹ 10,200 करोड़ (वित्त वर्ष 2018-19 में ₹ 5,200 करोड़ एवं वित्त वर्ष 2019-20 में ₹ 5,000 करोड़) तक के राशि की आवश्यकता को प्राप्त करने का अनुमोदन था। सरकार के सामान्य राजस्व पर अदायगी जिम्मेदारी सीमित है।
- (ii) **पब्लिक सेक्टर बैंकों में कैपिटल इंप्यूजन:** 2017-18 में ₹ 80,000 करोड़, 2018-19 में ₹ 1,06,000 करोड़, 2019-20 में ₹ 65,443 करोड़ 2020-21 में ₹ 17,364 करोड़ और 2021-22 में ₹ 4,600 करोड़ की राशि को पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) को पुर्नपुंजी प्रदान किया गया था।
- (iii) वार्षिकी परियोजना की देयता का विवरण प्राप्त बजट 2022-23 के भाग-ख में दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक अशोधित वार्षिकी देयता की राशि ₹ 39,927.66 करोड़ थी।